भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1356

02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए नियत

फेम 3.0 लॉन्च करने की योजना

1356. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग स्टेशनों आदि को और बढ़ावा देने के लिए फेम 3.0 शुरू करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) फेम 1.0 और 2.0 का कार्य निष्पादन/सफलता कैसी रही है;

(ग) क्या सरकार की कोई राष्ट्रीय चार्जिंग नीति बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसके कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में एसआईएएम के साथ कोई चर्चा की गई है, यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय वर्तमान में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तीव्रता लाने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:

i. 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की 6 माह की अवधि के लिए ₹778 करोड़ के परिव्यय वाली इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम-2024 जिसके अंतर्गत ई-दुपहिया और ई-तिपहिया वाहनों के खरीदारों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

ii. 25,938 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम। इस स्कीम के तहत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया, ई-बस और ई-ट्रक सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

iii. देश में उन्नत रसायन सेल के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय वाली उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम।

iv. वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को प्रमुख ई-वाहन विनिर्माता देश के रूप में बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन(एक्सईवी) के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम 2015 में तैयार की ताकि भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। 895 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ स्कीम का प्रथम चरण 31 मार्च, 2019 तक के लिए था। फेम इंडिया स्कीम के इस चरण में चार मुख्य क्षेत्र थे- तकनीकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग विनिर्माण घटक।

स्कीम के प्रथम चरण में, लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगभग 359 करोड़ रुपये का मांग प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा, स्कीम के प्रथम चरण में स्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को लगभग 280 करोड़ रुपये के राजकीय प्रोत्साहन के साथ देश के विभिन्न शहरों में तैनात किया गया। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के प्रथम चरण में लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों/बुनियादी ढांचे के लिए भी 43 करोड़ रुपये (लगभग) की मंजूरी दी थी।

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान -मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर, अलौह सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों को प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं आदि के लिए लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गईं, जैसे- बुनियादी परीक्षण ढांचे की स्थापना, विद्युतीकृत परिवहन, बैटरी इंजीनियरिंग आदि में उन्नत अनुसंधान के प्रयोजन से 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना।

फेम इंडिया स्कीम के पहले चरण के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर तथा उद्योग और उद्योग संघों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद सरकार ने कुल 11,500 करोड़ रुपये के बजटीय सहयोग से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम,चरण-।। को अधिसूचित किया।

चरण-II मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7,262 ई-बसों, 1,55,536 ई-तिपहिया वाहनों, 30461 ई-चौपहिया यात्री कारों और 15,50,225 ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना सृजन के लिए भी सहायता दी जाती है।

http://fame2.heavyindustries.gov.in/dashboard. aspx. के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम,चरण-II के तहत 31/07/2024 तक मूल उपकरण विनिर्माताओं (ईवी निर्माताओं) ने 16,71,606 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बतौर सब्सिडी प्रतिपूर्ति के तौर पर 6,825 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दावों का श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	संख्या वाहन की संख्या
1.	दुपहिया	14,69,343
2.	तिपहिया	1,78,952
3.	चौपहिया	23,311
	कुल	**16,71,606**

इसके अलावा, फेम-II स्कीम के तहत अंतःशहरी प्रचालन के लिए विभिन्न शहरों/एसटीयू/राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गईं। 6,862 ई-बसों में से 4,853 ई-बसों की तैनाती 31 जुलाई, 2024 तक की जा चुकी है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तीन तेल विपणन कंपनियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। तेल विपणन कंपनियों को 560 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, मार्च 2024 में भारी उद्योग मंत्रालय ने देश भर में नए चार्जर स्थापित करके 980 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना/उन्नयन के लिए फ़ेम-II के तहत तेल विपणन कंपनियों को अतिरिक्त 73.50 करोड़ रुपये मंजूर किए। तेल विपणन कंपनियों को 51.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******